(ग) राज्यों के अन्दर छोटे सम्पर्क

(घ) ऐसे अन्तरण जिनमें दो राज्य सम्मिलित हों

(ङ) ऐसे अन्तरण जिनमें दो से अधिक राज्य और अन्तर्राष्ट्रीय नदियां शामिल हों ।

15. आगे अन्वेषण प्रारम्भ करने से पहले प्रारम्भिक अध्ययनों पर आधारित राजनैतिक सहमति पर पहुंचने की आवश्यकता को पूर्वापेक्षित समझा गया ।

आदिवासी क्षेत्रों में फलोद्यान लगाया जाना

*199. श्री अजीत जोगी :
श्री राधाकिशन मालवीय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलोद्यान विकास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को फलोद्यान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई शेष प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है ताकि इन क्षेत्रों के गरीब आदिवासी किसानों को लाभ पहुंचे सके, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ख) मध्य प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं से आदिवासियों को लाभ पहुंचा है तथा इनसे कितने आदिवासियों को कितना लाभ पहुंचा है, और

(ग) इस संदर्भ में आगामी वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने मध्य प्रदेश में बागवानी के विकास की क्षमता के बारे में एक अध्ययन किया है । इस अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2025 तक बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा नामक आदिवासी जिलों में फलोद्यान के अंतर्गत 2,85,000 हैक्टेयर का विकास करना संभव होगा ।

(ख) केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत बस्तर में अन्नानस तथा काजू की खेती के लिए सहायता दी गई है ।

राज्य सरकार आदिवासी जिलों में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है :

(1) शहडोल, सरगुजा, बेतुल, बिलासपुर, होशंगाबाद, बस्तर, धाड़ और रायगढ़ नामक जिलों में फल रोपण राजसहायता योजना ।

(2) आदिवासी जिलों में कार्यान्वित की जा रही आदिवासी योज्य योजना के अंतर्गत सामुदायिक फलोद्यानों का विकास ।

(3) जवाहर रोजगार योजना—बस्तर, रायगढ़ तथा सरगुजा नामक आदिवासी जिलों में फल रोपण से संबंधित कार्यकलाप।

उपयुक्त योजनाओं से लगभग 5000 आदिवासियों को लाभ मिल रहा है ।

(ग) केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत 5 वर्षों में 400 हैक्टेयर (अन्नानस द्वारा) कवर करने तथा प्रति वर्ष 100 हैक्टेयर (काजू द्वारा) कवर करने की सम्भावना है ।

1992–93 में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 2100 हैक्टेयर तथा फल रोपण राजसहायता योजना के अंतर्गत 650 हैक्टयर क्षेत्र कवर करने का लक्ष्य रखा गया है ।

Settng up of an aluminium plant in Orissa

*200. SHRI BASANT KUMAR DAS: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether the Government of Orissa has sent a proposal for setting up an aluminium plant in the State;

(b) if so, the location thereof; and

(c) what steps Government have taken so far in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (INDEPENDENT CHARGE) (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) No. Sir.

(b) and (c) Do not arise.

New incentive scheme for sugad plants

@792 SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any new incentive scheme for sugar plants after the withdrawal of the scheme for *sugi.v* plants licensed during the seventh ;lan period in September, 1990;

(b) if jo, what are the details thereof;

(c) if the answer to part (a) above be in th/; negative, when a new incentive scheme is likely to be announced;

(d) whether Government proposes to give priority to capacity expansion of sugar factories in the country beyond 5000 tonnes a day by lifting the embargo placed on expansion during the seventh plan; and

(e) if so, what is the deciison, if any, taken by Government in this regard stating (I) the total number of capacity expansion applications pending clearance at the end of 1990; and (ii) when these applications are likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (INDEPENDENT CHARGE) (SHRI TARUN GOGOI): (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

(c) The formulation of a new incentive scheme is under consideration of the Government.

©Previously Unstarred Question No. 345, transferred from 18-7-91.

(d) and (e) As on 31.12.1990, 30 applications for expansion of capacity were pending consideration of the Government. The Licensine Police lines for sugar industry are presently being reviewed by the Government. These applcations would be policy formulated after the aforesaid review.

Production of pulses

793. SHRI R. T. GOPALAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the assistance given by the Central Government to Tamil Nadu in the form of quality seeds of pulses during the years 1989-90 and 1990-91 so far;

(b) the production of pulses during the year 1989-90 and the target fixed for 1990-91; and

(c) the quantity of pulses imported during 1989-90?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) Government of India provided an assistance of Rs. 15.12 lakhs during 1989-90 and of Rs. 22.70 lakhs for 1990-91 for the production and distribution of quality seed to Tamil Nadn state under the National Pulses Development Prrogramme. (NPDP).

(b) The production of pulses during 1989-90 was 12.61 million tonnes, while the target for the year 1990-91 15.0 million tonnes.

(c) 4.29 iakh tonnes of Pulses were imported during 1989-90.

Decongestion of bigger cities

794. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to decongest the biggest cities which are overcrowded; and